हरियाणा सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हरियाणा बजट 2022-2023

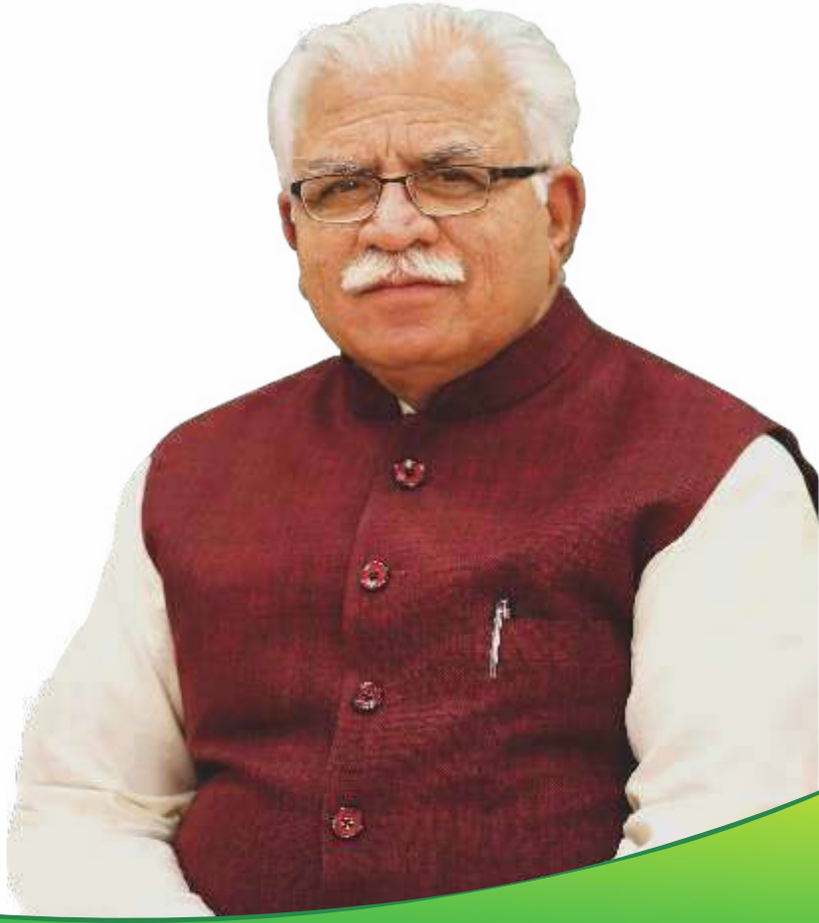

बजट 2022-23

हरियाणा सरकार

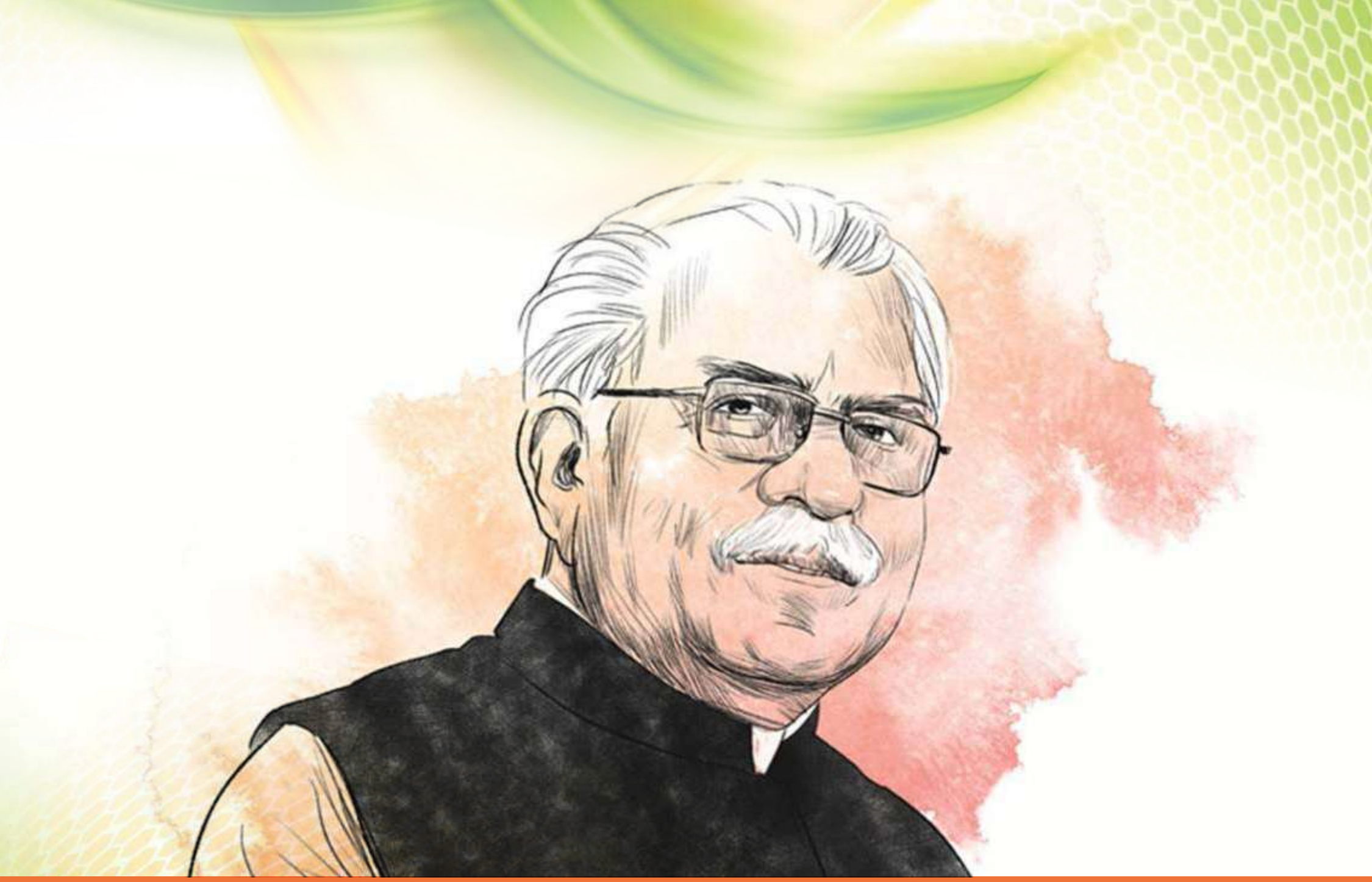

श्री मनोहर लाल, वित्तमंत्री हरियाणा

बजट 2022-23

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
1	बजट की मुख्य विशेषताएं	01
2	बजट सरांश	03
3	मुख्य आवंटन	11
4	महिला सशक्तिकरण	13
5	कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	13
6	सहकारिता	14
7	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	15
8	वन	15
9	शिक्षा	15
10	स्वास्थ्य	16
11	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	17
12	बाल विकास	18
13	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	18
14	रोजगार	18
15	श्रम	19
16	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	19

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
17	सभी के लिए आवास	19
18	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	20
19	खेल एवं युवा मामले	20
20	सैनिक एवं अर्ध सैनिक	20
21	औद्योगिक विकास	21
22	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	21
23	सिंचाई एवं जल संसाधन	22
24	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	22
25	विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा	22
26	परिवहन	23
27	नागरिक उड्डयन	23
28	पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय	24
29	आबकारी एवं कराधान	24
30	पर्यटन, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति	25
31	शासन एवं लोक प्रशासन	25
32	पुलिस	26

बजट की मुख्य विशेषताएं (Main Features of Budget)

आत्मनिर्भर भारत के विज़न को पूरा करने के लिए वर्ष–2047 तक की यात्रा में भारत माता की नियति को आकार देने के अपने सामूहिक संकल्प और दृढ़ निश्चय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सरकार इस कार्यकाल के बजट को 'वज्र बजट' के रूप में प्रस्तुत कर रही है। अपने पिछले बजट में, सरकार ने एक जीवंत और समृद्ध हरियाणा के लिए चार प्रमुख रणनीतियों पर आधारित एक विज़न पेश किया था, जिनमें प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, मध्यावधि व्यय ढांचे–रिजर्व फंड का निर्माण करना, परिणामोन्मुखी विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था।

कोविड–19 महामारी के कारण देश के पिछले दो वर्ष चुनौतीपूर्ण रहे हैं। वर्ष 2022–23 के बजट के मुख्य बिन्दु हरियाणा की पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करना व विकास के वज्र मॉडल को प्रस्तुत करना है। केंद्र सरकार ने सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु क्रियाशीलता के चार स्तंभों और निजी एवं सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देकर **'अमृत काल'** के रूप में अगले 25 वर्षों में देश की विकास यात्रा को जारी रखने का संकल्प लिया है।

हरियाणा की पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करना

- सरकार का ध्यान कोरोना से उबरने के लिए मुद्रा प्रसार प्रति–चक्रीय राजकोषीय (Counter Cyclical Fiscal) उपायों पर केन्द्रित रहा है।
- अंत्योदय की भावना से गरीब से गरीब का कल्याण, प्रभावी आय पुनर्वितरण रणनीतियों के साथ उत्पादकता में वृद्धि और रोज़गार एवं उद्यमिता का सृजन ही सरकार की प्राथमिकता है।
- अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए पूंजी अवसंरचना (Capital Infrastructure) निवेश बढ़ाने पर विशेष बल।
- सरकार का दृष्टिकोण विकेन्द्रीकृत शासन और नागरिक – केंद्रित आर्थिक वृद्धि एवं विकास को मजबूत करना है।

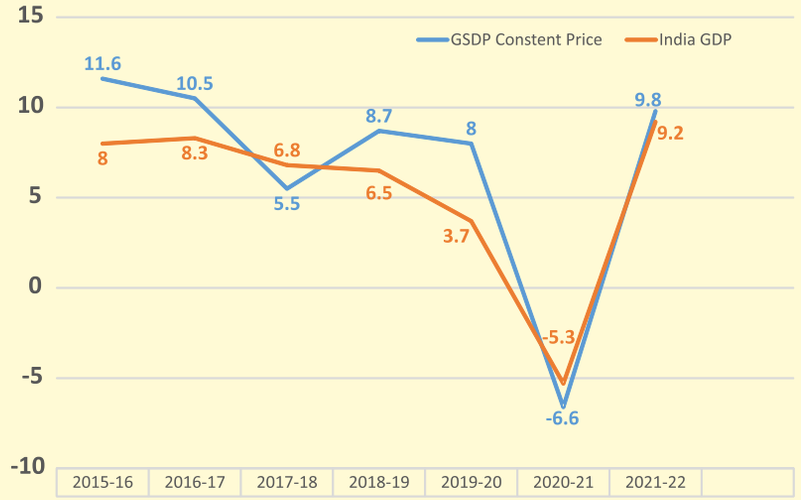

Haryana GSDP Growth at Constant (2011-12) Prices (%)

हरियाणा के विकास का वज्र (डायमंड) मॉडल

यह बजट हरियाणा के विकास का **'वज्र मॉडल'** प्रस्तुत करता है, जिसमें आर्थिक विकास तथा मानव विकास नागरिकों के जीवन की सुगमता, विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों के गरीबों के उत्थान के लिए पांच शक्तियों की परिकल्पना की गई है। ये शक्तियां इस प्रकार हैं:–

1. समर्थ हरियाणा – सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार।
2. अंत्योदय – गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान
3. सतत् विकास – सस्टेनेबल डेवलपमेंट
4. संतुलित पर्यावरण – पर्यावरणीय स्थिरता
5. सहभागिता – सार्वजनिक व निजी भागीदारी (जी.सी.पी.)

बजट सारांश (BUDGET SUMMARY)

- वर्ष 2022–23 (BE) 177255.99 करोड़ रुपये का कुल खर्च (Total Expenditure), वर्ष 2021–22 (RE) 153384.40 करोड़ रुपये, से 15.6 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 2014–15 से 2021–22 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।
- वर्ष 2021–22 में प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) का योगदान 17.2 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) का योगदान 35.3 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) का योगदान 47.5 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2021–22 संशोधित बजट (RE) Debt to GSDP अनुपात 24.98 प्रतिशत रहा जोकि 15 वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 32.6 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत है।
- इस बजट परिव्यय में 61,057.35 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) और 1,16,198.63 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) शामिल है, जोकि क्रमशः 34.4 प्रतिशत और 65.6 प्रतिशत है।
- इस वर्ष के बजट आवंटन को सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) के साथ भी जोड़ा है। 1,77,255.98 करोड़ रुपये के कुल बजट में से सतत् विकास लक्ष्य से संबंधित योजनाओं के लिए 1,14,444.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- कोविड–19 महामारी के संकट के बावजूद बाजार से लगभग 30,820 करोड़ रुपये की ही उधारी ली है, जबकि पंद्रहवें वित्त आयोग से हमें 40,872 करोड़ रुपये की उधारी की अनुमति थी।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

- राजकोषीय घाटा वर्ष 2021–22 में GSDP का 2.99 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, यह कम होकर 2.98 प्रतिशत अनुमानित है। यह पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।

राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

- राजस्व घाटा भी निरंतर कम हो रहा है। यह संशोधित अनुमान 2021–22 में 1.40 प्रतिशत अनुमानित है।
- बजट अनुमान 2022–23 में यह GSDP के 0.98 प्रतिशत तक और कम होने का अनुमान है।

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)

- पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- वर्ष 2021–22 में इसे बढ़ाकर 48,265.49 करोड़ रुपये किया है, जिस से कुल व्यय में पूंजीगत हिस्सा बढकर 31.5 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2022–23 में पूंजीगत हिस्सेदारी को 34.4 प्रतिशत बढाकर प्रदेश के पूंजीगत व्यय को 61,057.35 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
- पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय आवंटन के अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी राज्य में पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश कर रहे हैं।
- वर्ष 2022–23 में 5327.56 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की संभावना है। इसलिए, बजट अनुमान 2022–23 में Cumulative Capital Investment 66,384.91 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इन्हीं का ही परिणाम है कि पिछले 5 सालों में इनका Cumulative Profit Margin लगभग 3 गुणा हो गया है। यह 562.88 करोड़ रुपये से बढ़कर 1393.04 करोड़ रुपये हो गया है।
- सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

समर्पित कोष (Dedicated Fund)

- राजकोषीय अपव्यय से बचने के लिए 3 समर्पित कोष स्थापित किये जाएंगे।
  - हरित विकास उद्देश्यों के लिए **'जलवायु एवं सतत् विकास कोष'**।
  - वैज्ञानिक गतिविधि और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए **'अनुसंधान एवं नवाचार कोष'**।
  - स्टार्ट–अप की सहायता के लिए **'उद्यम पूंजी कोष'**।

बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार (Reforms in Budgetary Processes)

- इस वर्ष बजट प्रक्रिया में 2 बड़े बदलाव किये हैं।
  - विभिन्न विभागीय आवंटनों को नई तर्कसंगत बजटीय मांगों से जोड़ा है।
  - स्वायत्त संस्थानों द्वारा सम्पत्ति पर व्यय के लिए लेखांकन प्रणाली में सुधार किया है।
- सरकारी संस्थाओं को पोर्टफोलियो प्रबंधन और कम लागत वाली कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में 'हरियाणा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड' की स्थापना की है।
- समाज के कमजोर वर्गों को बीमा लाभ प्रदान करने के लिए एक 'बीमा न्यास' भी स्थापित किया गया है।

बजट एक नजर (BUDGET AT A GLANCE)

राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़)
Revenue Receipts (₹ Crore)

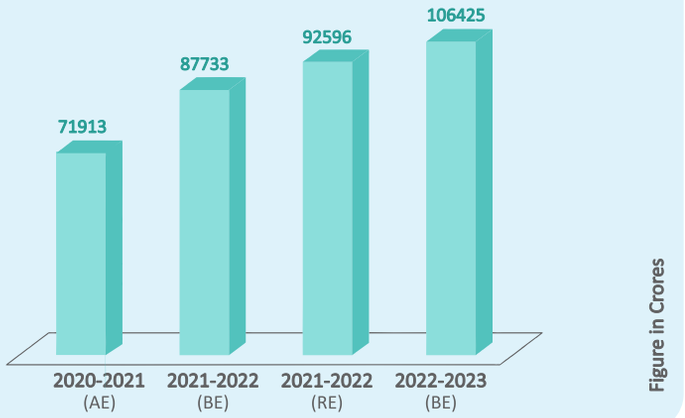

पूंजी प्राप्तियां (₹ करोड़)
Capital Receipts (₹ Crore)

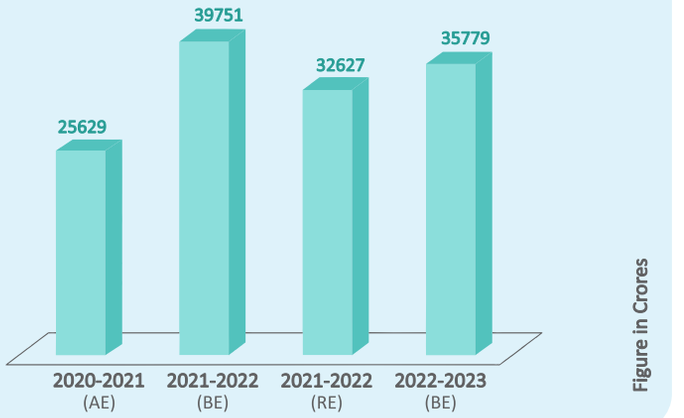

राजस्व व्यय (₹ करोड़)
Revenue Expenditure (₹ Crore)

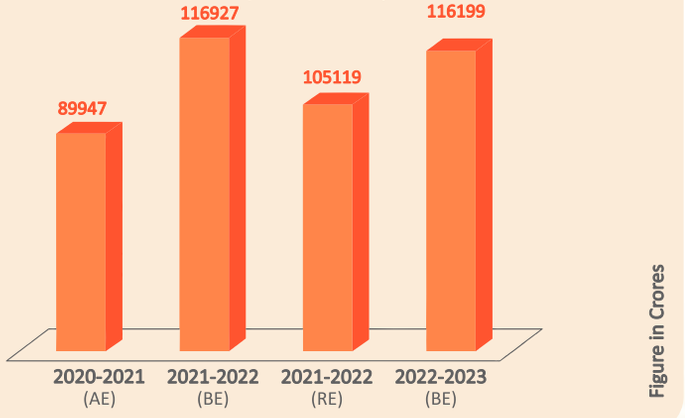

प्रभावी पूंजीगत व्यय (₹ करोड़)
Capital Expenditure (₹ Crore)

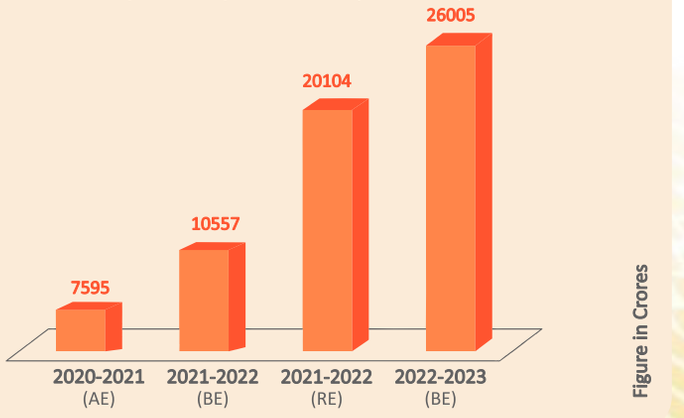

*AE - Actual Estimate | *BE - Budget Estimate | *RE - Revised Estimate

कैसे आता है रुपया (Rupee Comes From) %

- राज्य का अपना कर राजस्व (43.71)
  State's Own Tax Revenue
- गैर कर राजस्व (7.28)
  Non Tax Revenue
- अन्य प्राप्तियां (3.95)
  Other Receipts
- केंद्र से विचलन (12.22)
  Devolution from Centre
- उधार (32.84)
  Borrowings

कैसे आता है रुपया (Rupee Comes From) %

केंद्र से विचलन (Devolution from Centre) 12.22

केन्द्र से प्राप्त सी.एस.एस. हिस्सा और अन्य अनुदान (Central share under CSS and other Grants)	6.90
केन्द्रीय करों का हिस्सा (Share of Central Taxes)	5.32

उधार (Borrowings) 32.84

राज्य विकास ऋण (State Development Loan)	20.88
खाद्यान खरीद (Food Procurement)	8.83
NABARD और NCRPB (NABARD and NCRPB)	1.17
अर्थोपाय (Ways and Means)	0.87
भारत सरकार से ऋण (GoI Loan)	0.78
अन्य (Others)	0.31

राज्य का अपना कर राजस्व (State Own Tax Revenue) 43.71

एस.जी.एस.टी. (SGST)	19.58
वैट (VAT)	8.41
स्टेट एक्साइज (State Excise)	7.18
स्टांप और पंजीकरण (Stamps and Registration)	5.80
वाहन कर (Taxes On Vehicles)	2.65
अन्य (Others)	0.09

गैर कर राजस्व (Non Tax Revenue) 7.28

परिवहन (Transport)	1.79
खान एवं भूविज्ञान (Mines and Geology)	1.25
शहरी विकास (Urban Development)	1.16
शिक्षा (Education)	0.51
अन्य (Others)	1.56

अन्य प्राप्तियां (Other Reciepts) 3.95

कैसे जाता है रुपया (Rupee Goes To) %

- सामाजिक सेवाएं (32)
  Social Services
- आर्थिक सेवाएं (22.12)
  Economic Services
- सामान्य सेवाएं (14.09)
  General Services
- ऋण भुगतान (31.79)
  Repayment of Debt

कैसे जाता है रुपया (Rupee Goes To) %

आर्थिक सेवाएं (Economic Services) 22.12

कृषि सिंचाई व अन्य (Agriculture & Allied including Irrigation & RE Subsidy)	10.58
ग्रामीण विकास और पंचायतें (Rural Development & Panchayats)	3.88
परिवहन, नागरिक उड्डयन, सड़कें और पुल (Transport, Civil Avaition, Roads & Bridges)	3.68
अन्य (Others)	3.98

सामान्य सेवाएं (General Services) 14.09

पेंशन (Pension)	6.87
प्रशासनिक सेवाएं (Administrative Services)	4.50
अन्य (Others)	2.72

ऋण भुगतान (Repayment of Debt) 31.79

मूलधन (Principal)	19.78
ब्याज़ (Interest)	12.01

सामाजिक सेवाएं (Social Services) 32.00

शिक्षा (Education)	11.12
समाज कल्याण और पोषण (Social Welfare & Nutrition)	6.82
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (Health & Family Welfare)	4.85
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (Public Health Engineering)	2.55
अन्य (Others)	6.66

मुख्य आवंटन (MAJOR ALLOCATION)

	2021-22 (RE) रुपये करोड़	2022-23(BE) रुपये करोड़
शिक्षा, खेल,कला एवं संस्कृति (Education Sports, Art and Culture)	17261	20445
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता,महिला एवं बाल कल्याण और अनुसुचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण (Social Justice and Empowerment, WCD and Welfare of SCs & BCs)	10863	13050
पेंशन (Pension)	10801	11201
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ई.एस.आई., खाद्य एवं औषधि (Health, Medical Education & Family Welfare, Ayush ESI, Food & Durgs)	7614	8926
शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन (Urban Development and Town & Country Planning)	9193	8468
विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा (Power and Non Conventional Energy)	7876	7203
पंचायत एवं ग्रामीण विकास (Panchayat and Rural Development)	3724	6826
गृह (Home)	6057	6526

मुख्य आवंटन (MAJOR ALLOCATION)

	2021-22 (RE) रुपये करोड़	2022-23(BE) रुपये करोड़
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (Agriculture & Allied Activites)	5206	6497
सिंचाई एवं जल संसाधन (Irrigation and Water Resources)	4064	6136
लोक निर्माण,सड़क और पुल (Public work, Roads and Bridges)	4199	4752
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (Public Health Engineering)	3899	4554
परिवहन (Transportation)	2902	3708
सहकारिता (Cooperation)	2068	1537
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (Technical Education and Skill Development)	896	1105
उद्योग एवं वाणिज्य (Industry and Commerce)	456	598

हरियाणा सरकार

बजट 2022-23

महिला सशक्तिकरण

- महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये की नकद राशि वाला 'सुषमा स्वराज पुरस्कार'।
- महिला उद्यमियों के लिए 'हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता' योजना।
- कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला में नये आवास।
- जिला भिवानी के कुडल व छापर तथा जिला सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज।
- उन स्वयं सहायता समूह के ऋण की सम्पूर्ण ब्याज राशि सरकार वहन करेगी, जिनके आधे से अधिक सदस्यों के परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र

- प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 कलस्टर में 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम'।
- मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण हेतु भिवानी में 'क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र' की स्थापना।
- जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिला–सिरसा और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन।
- नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए एच.एस.ए.एम.बी. को 200 करोड़ रुपये का अनुदान।
- गर्मी सीजन की मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर।
- 'फसल समूह विकास कार्यक्रम' के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना।
- 'फसल विविधिकरण कार्यक्रम' के तहत 20,000 एकड़ में फसल विविधिकरण का लक्ष्य।

- किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना।
- किसानों के मार्गदर्शन के लिए 'प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन' कार्यक्रम।
- 'एम्ब्रयो ट्रांसफर टैक्नॉलोजी' (ई.टी.टी.) से पैदा होने वाले बछड़ों पर 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि।
- अंत्योदय परिवार जिनके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि या स्थान नहीं है, उन परिवारों को ग्राम पंचायत की भूमि पर एक सांझा शैड की सुविधा।
- मत्स्य पालकों को भी 'किसान क्रेडिट कार्ड' की सुविधा।
- भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क–सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- गुरुग्राम में सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम होगा स्थापित।
- पशुपालन व डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए एक लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद का लक्ष्य।
- मत्स्य पालकों को भी 'किसान क्रेडिट कार्ड' की सुविधा।

सहकारिता

- प्रदेश में हैफेड द्वारा 'गुड़ इकाइयां' स्थापित करने का निर्णय।
- सभी जिलों में दूध और दुग्ध व अन्य खाद्य उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं।
- 'एकमुश्त निपटान योजना' के तहत 30 नवम्बर, 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋणों की मूल राशि का भुगतान करने पर किसानों की दण्डात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ।

हरियाणा सरकार

बजट 2022-23

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

- प्रदूषण कम करने के लिए हर जिले में हॉट स्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदलने का लक्ष्य।
- प्रमुख पर्यावरणविद् श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर 3 लाख रुपये तक का पुरस्कार।
- प्रदेश में 100 'वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र'।

वन

- ईको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 'ईको–टूरिज्म नीति'।
- हर वृक्ष की गिनती के लिए वृक्ष–गणना और जियो टैगिंग।
- कालका से कलेसर तक 150 कि.मी. लम्बी 'नेचर ट्रेल' की स्थापना।
- प्रदेश में 10 नई हाइटेक नर्सरियां विकसित करने का निर्णय।

शिक्षा

- नूंह में नये बहु–विषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना।
- बेटियों को सुरक्षित व सुलभ परिवहन सुविधा के लिए 'साथी' योजना।
- 'स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम' के तहत 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य की जांच।
- अगले तीन वर्षों में 362 नये संस्कृति मॉडल स्कूल।
- कौशल को बढ़ावा देने के लिए एस.टी.ई.एम. लैब की स्थापना।

- 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड व पुरस्कार।
- सरकारी स्कूलों में पढने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट।
- सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ट्विनिंग प्रोग्राम।
- शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को हैडमास्टर, हैड टीचर व प्राचार्य का प्रशिक्षण।
- प्राचीन भाषाओं और हस्तलिपि में सीखने, अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान।
- उन्नत एवं उभरती प्रोद्योगिकियों में शिक्षा और शोध को बढावा देने के लिए मानेसर में 'इंस्टीच्युट ऑफ इमर्जिंग टेक्नॉलाजी की स्थापना।

स्वास्थ्य

- उप–मण्डलीय अस्पतालों को ऑक्सीजन सुविधा सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड करना।
- वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक वाले परिवारों को 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ।
- वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक वाले परिवारों के 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगजनों को 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ।
- अस्पतालों को 'आयुष्मान भारत योजना' के इलाज की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर।
- वार्षिक आय 1.80 लाख तक वाले परिवारों को 2 वर्ष में एक बार नि:शुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच सुविधा।

- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 40 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा के डॉक्टरों हेतु आरक्षित।
- सभी जिला नागरिक अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में विश्राम सराय की सुविधा।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला नागरिक अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर।
- छोटे कस्बों और बड़े गांवों में अस्पताल व नर्सिंग होम खोलने पर 3 वर्ष तक ऋण के ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट।
- हर खण्ड में टी.बी. जांच के लिए मॉलिक्यूलर टैस्टिंग लैब की सुविधा।
- गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल युनिटस शुरु करने का निर्णय।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

- PGIMS, रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा।
- कैथल, सिरसा और यमुनानगर में नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य आरम्भ।
- पलवल, चरखी–दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में नये मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा।
- जींद, भिवानी, महेन्द्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी–दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेजों के साथ नये नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय।
- तकनीकी विश्वविद्यालयों व मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर चिकित्सा प्रौद्योगिकी व जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग में संयुक्त डिग्री शुरू करने का निर्णय।
- ऐलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।

बाल विकास

- आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली।
- 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना' योजना का लाभ अब दूसरे बच्चे पर भी।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

- 'गुरु–शिष्य योजना' के तहत 25000 गुरु व 75000 शिष्यों सहित एक लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य।
- सरकारी कालेजों व सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण व प्रमाणन को शामिल करने का निर्णय।
- औद्योगिक क्षेत्रों में 'दोहरी ट्रैक प्रणाली' के तहत कौशल प्रशिक्षण केन्द्र।
- 'दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली' से 44 नई ट्रेड यूनिट्स को जोड़ना।

रोजगार

- निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 200 रोजगार मेलों का लक्ष्य।
- अगले 2 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलवाने के लिए 'हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सैल' की स्थापना।
- अनुबंधित मानव शक्ति को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन।

हरियाणा सरकार

बजट 2022-23

श्रम

- श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, हिसार, रोहतक और जींद में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं।
- प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले 6 ई.एस.आई. अस्पतालों और 14 ई.एस.आई. औषधालयों की स्थापना।
- बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को निजी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा।
- गुरुग्राम और फरीदाबाद में बाल श्रम पुनर्वास केन्द्र।
- प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और पानीपत में 4 नये स्कूल खोलने का निर्णय।
- ई.एस.आई.सी. औषधालयों में एक्सरे मशीन, लैब व उपकरण की सुविधा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

- मानसिक दिव्यांगों के लिए अम्बाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना।
- एड्स पीड़ितों को 2250 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता।
- डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार शामिल।

सभी के लिए आवास

- 'प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी' में 20,000 नये घरों का निर्माण।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति

- पात्र परिवार जिनके पास बी.पी.एल. या ओ.पी.एच. राशन कार्ड नहीं है, उन्हें पी.डी.एस. के लाभार्थियों में शामिल करने का लक्ष्य।
- उचित मूल्य की दुकानों को सांझा सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य करने का विकल्प।

खेल एवं युवा मामले

- ओलंपिक में देश के एक–तिहाई पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते।
- राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना।
- प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां खोलने का लक्ष्य।
- 'खेल अकादमी' योजना में 10 डे–बॉर्डिंग और 8 आवासीय अकादमियां खोलने का लक्ष्य।
- रोजगार में मदद के लिए 1,000 युवाओं को साहसिक खेल गतिविधियों का प्रशिक्षण।
- हरियाणा को मिली चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी।

सैनिक एवं अर्ध सैनिक

- राज्य में सभी पूर्व अर्ध सैनिक बलों को पंजीकृत करके पूर्व सैनिकों के समान लाभ देने का निर्णय।
- सभी जिलों में एकीकृत सैनिक एवं अर्ध सैनिक सदन खोलने का निर्णय।

औद्योगिक विकास

- आई.एम.टी. के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान।
- आई.एम.टी. सोहना में 662 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण कलस्टर की स्थापना को मंजूरी।
- इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'क्षेत्रीय प्रोत्साहन नीति'।
- एम.एस.एम.ई. उद्योगों को प्राकृतिक गैस पर एकत्रित वैट पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।
- एन.सी.आर. में एम.एस.एम.ई. के बॉयलरों को स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए 15 लाख रुपये तक अनुदान।
- निर्यात को बढावा देने के लिए माल ढुलाई सब्सिडी।
- गैर–जोखिम उद्योगों का अग्नि सुरक्षा निरीक्षण 3 वर्षों में एक बार।
- परम्परागत उद्योगों के पुन : उद्धार के लिए 'राज्य लघु पुनरुत्थान योजना कोष' की पहल।
- छोटे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए 'लघु उद्यमिता सहायता कोष' की स्थापना।
- हर जिले में साल में एक बार 'जिला व्यापार मेलों' का आयोजन।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)

- प्रदेश में 22 रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अण्डरपास बनाने का लक्ष्य।

सिंचाई एवं जल संसाधन

- गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए 5000 रिचार्ज बोरवैल के निर्माण का लक्ष्य।
- माइनरों पर पुलों के निर्माण के लिए दूरी का मानदंड 1,000 मीटर से कम करके 500 मीटर।
- पक्के खालों की मरम्मत के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत सूक्ष्म सिंचाई की शर्त में ढील।
- 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई' योजना के 'प्रति बूंद अधिक फसल' घटक में 1214 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान।
- नूंह और गुरुग्राम जिलों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 200 क्युसिक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- जल जीवन मिशन के तहत 19 जिलों में घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य पूरा। शेष 3 जिलों–जींद, पलवल में नूंह में जल्द होगा पूरा।

विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा

- औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार व उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश।
- जिन सरकारी भवनों में बिजली की मांग 10 किलोवॉट या उससे अधिक है, उनमें अगले दो वर्षों में रूफ टाप या अन्य सौर प्रणालियों से बिजली का प्रावधान।

- सरकारी कार्यालयों में 'प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम' लागू करने का निर्णय।
- प्रदेश में 75 प्रतिशत सब्सिडी पर 10 एच.पी. तक के 50,000 सोलर पंप।
- गांवों में जैव ऊर्जा संयंत्रों के लिए 'मैचिंग ग्राण्ट' स्कीम।
- प्रदेश के 5569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, शेष गांवों में वित वर्ष 2022–23 में 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने का लक्ष्य।

परिवहन

- रोडवेज बेड़े में 2,000 नई बसें जोड़ने का लक्ष्य।
- सभी बसों में इलेक्ट्रोनिक टिकट प्रणाली।
- लोगों को प्वाइंट–टू–प्वाइंट परिवहन सुविधा के लिए नई 'मैक्सी कैब' नीति।
- गुरुग्राम के खेड़कीदौला में मल्टी मॉडल सुविधा युक्त नये 'बस पोर्ट' की स्थापना।

नागरिक उड्डयन

- फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु ;ण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गांरटी योजना।
- करनाल व भिवानी हवाई पट्टियों की लम्बाई 3000 फुट से बढाकर 5000 फुट करना।
- नारनौल में हवाई पट्टी पर 'नाइट लैडिंग' की सुविधा।

पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय

- जिला परिषदों को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत।
- ग्रामीण सड़कों की मरम्मत व रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषदों को।
- ग्रामीण खंडों और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढाने के लिए मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम।
- शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विकास के लिए 'दिव्य नगर' योजना।
- गांवों में पुस्तकालय स्थापित करने की योजना।
- रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक बस की पायलट योजना सहित संगठित नगर परिवहन सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य।
- सभी जिलों में ई–लाइब्रेरी सुविधा युक्त जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय।
- अग्निशमन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए बजट में 5 गुणा बढ़ोतरी।

आबकारी एवं कराधान

- पुराने वैट बकाया के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना।

पर्यटन, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति

- सिखों की राजधानी लौहगढ को पर्यटन केन्द्र के रूप में उभारने के लिए एक सिख हैरिटेज संग्रहालय व एक मार्शल आर्ट संग्रहालय की स्थापना।
- गुरुकुल, झज्जर के स्वामी ओमानन्द जी के नाम पर राजकीय संग्रहालय की स्थापना।
- प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में हैरिटेज कार्नर स्थापित करने का लक्ष्य।
- सरस्वती को पुन : धरा पर लाने के लिए आदिबद्री में सोम नदी पर बांध का निर्माण।
- सूरजकुंड में नवम्बर मास में एक और शिल्प मेला आयोजित करने का निर्णय।
- जिला फतेहाबाद के कुणाल में पूर्व हड़प्पा स्थल पर संग्रहालय की स्थापना।

HARYANA TOURISM
Come, holiday with us !

शासन व लोक प्रशासन

- बीमा कवर प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना।
- ऐसे कर्मचारी जो अपनी सेवा के दौरान कम से कम 70 प्रतिशत दिव्यांग हो जाते हैं, उन्हें एक्स ग्रेशिया के नियमों के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति।

पुलिस

- प्रदेश के 381 पुलिस स्टेशनों व 357 पुलिस चौकियों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का लक्ष्य।
- प्रदेश में 21 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य।
- हरियाणा पुलिस में महिलाओं का प्रतिधित्व 15 प्रतिशत करने के लिए 1000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती का निर्णय।
- पुलिसकर्मियों के लिए 2000 नए मकान बनाने का लक्ष्य।

नोट

नोट

नोट

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

बजट 2022-23

कृषि कल्याण

आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

परिवार पहचान-पत्र

ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस

महिला सशक्तिकरण

सुशासन से सेवा

समग्र शिक्षा

जल संरक्षण

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा
www.prharyana.gov.in | @diprharyana